displayed at stations, are also called at the time of emergency.

सांची के स्तूप

661. श्री रामवजी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांची (मध्य प्रदेश) में स्थित अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात स्तूपों के रात्रि के समय प्रकाशित करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई): (क) जी, नहीं।

(ख) सांची के स्मारक एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है और इस स्मारक को रात के समय प्रकाशित करने से पर्यटक आकर्षित नहीं होंगे। इस स्मारक को सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है। ताजमहल तथा आगरा के स्मारकों की जलवायु एवं पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता और परिरक्षण से संबद्ध विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट इन स्मारकों को प्रकाशित करने की सिफारिश नहीं करती है।

नरभक्षी भेड़ियों द्वारा ली गई जानें

662. श्री महेश्वर सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1996 के इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) में "वन डाउन, थ्री टू गो: किलर वूल्फ शाट डेड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में नरभक्षी भेड़ियों की संख्या कितनी है और उनके द्वारा कितने लोगों की जान ली गई;

(ग) क्या सरकार ने मृतकों के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि प्रतापगढ़, जौनपुर और सुलतानपुर जिलों में 17.3.1996 और 6.7.1996 के बीच भेड़िए के एक झुंड ने 21 बच्चों को मार दिया था।

(ग) और (घ) उन्होंने यह भी बताया है कि जौनपुर जिले में मृतकों के 5 मामलों और घायलों के 9 मामलों में 34,000 रु॰ वितरित किए गए हैं। जबकि प्रतापगढ़ और सुलतानपुर जिलों में अभी तक कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी गई है।

(ङ) राज्य प्राधिकारियों ने भेड़ियों और उनके व्यवहार तथा किए जाने वाले एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उक्त क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया है।

Import of Urea

663. SHRIRAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Financial Express dated 1.7.1996 captioned "Rs. 52 crore Urea blocked at ports-delay in off loading costs exchequer $ 25,000 per day" by way of demurrage charges;

(b) if so, what are the details thereof indicating who placed the order for import of urea and when despatch orders from Government to its assigned destinations were issued; and

(c) what action Government have so far taken against the defaulters for such huge losses to exchequer and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) to (c) Yes, Sir. The contracts for import of urea were concluded by the canalising agents in accordance with the advance authorisation given to them month-wise by the Government. Two vessels, "Prabhu Gopal" and "Jag Ravi" which sailed on 9.6.96 and 17.6.96 respectively from Shuiaba, were directed to proceed to Tuticorin on 17.6.96 and Rosy on 21.6.96 respectively. As on 1.7.96, these vessels were awaiting commencement of discharge for want of designated handling agencies.

The Government had started the process of appointment of handling agencies well in time. But unlike in the past, the rates received through tenders for handling urea at the ports during 1996-97 were uniformally higher over